

प्रबंधन मरीजों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे-कलेक्टर

मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल का निरीक्षण करके कहा-क्रमबद्ध समस्याएं होंगी दूर

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इसके पहले कलेक्टर ने बैठक लेकर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की और चिकित्सा व्यवस्था सहित अन्य जानकारी ली।



विशेष पिछड़ी जनजातियों का रखें ध्यान

निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे कलेक्टर अजीत वसंत ने विशेष पिछड़ी जनजाति के मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी कोरवा, पंडो जनजाति विशेष के मरीजों को किसी प्रकार की जांच सुविधा के लिए भटकना न पड़े, इस कार्य में अस्पताल के कर्मचारी सहयोग करें।

समन्वय स्थापित करके समस्या करेंगे दूर

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला अस्पताल के हमर लैब में रिजेंट की उपलब्धता नहीं रहने से जांच में आने वाली दिक्कतों के परिप्रेक्ष्य में किए गए सवाल पर कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करके इस समस्या को दूर किया जाएगा। एनओसी की प्रक्रिया के कारण दिक्कत की स्थिति बनती है। स्थानीय स्तर पर खरीदी के लिए पूर्व में दिए गए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि इसके लिए सीजीएमएससी से एनओसी लेकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अस्पताल परिसर के आसपास ठेले-गुमटी के बेतरतीब लगने से होने वाली दिक्कतों के सवाल उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने कहा है।

सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हों। साथ ही चिकित्सालय में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया एवं चिकित्सालय के भवन में सीपेज प्रबंधन हेतु भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निगम के निर्माणाधीन कार्यालय को जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश

सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं और जल शोधन संयंत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।



कलेक्टर ने सबसे पहले नगर पालिक निगम के निर्माणाधीन नवीन कार्यालय भवन का जायजा लिया। इस भव्य भवन का निर्माण 783.05 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। कार्य की प्रगति देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और टेकदारों को निर्देशित किया कि भवन का शेष कार्य जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। इसके पश्चात कलेक्टर ने कतकाली स्थित 15 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया, और पेयजल की महत्ता को देखते हुए अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में शहरवासियों को जल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से ही सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी घटक के तहत वार्ड क्रमांक 02, सुभाषनगर में बन रहे आवासों का भी अवलोकन किया। यहां 22.04 करोड़ रुपये की लागत से कुल 17 ब्लॉकों में 493 आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है। उन्होंने आयुक्त और अभियंताओं को निर्देश दिया कि कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर शीघ्र ही हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाएं। स्थल पर सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही आवास परिसर में अन्य नागरिक सुविधाओं को विकसित करने पर चर्चा की।

आर.सी. आर्या, मुख्य सौजीएमएससी की टीम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अस्पताल सलाहकार स्वस्तिका अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी, डीपीएम डॉ. पुष्पेंद्र, कर्मचारी उपस्थित थे।

शांति व्यवस्था बनाए रखने सर्व धर्म एकता मंच ने आईजी को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सर्व धर्म एकता मंच के प्रतिनिधियों ने बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को क्रिसमस त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं धर्म विशेष के त्योहार के दौरान इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें उल्लेख किया गया है कि सर्व समाज और चैम्बर ऑफ कामर्स के द्वारा धर्म विशेष के खिलाफ 24 दिसम्बर, बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य बंद का आह्वान किया गया। 25 दिसम्बर को देशभर में मसीही समुदाय के लोग प्रभु ईसा का जन्मदिवस हर्षोल्लास मनाते हैं। प्रभु ईसा के जन्म का धार्मिक रस्म 24 दिसम्बर से ही शुरू हो जाता है, और 25 दिसम्बर की शाम को समाप्त होता है। ऐसे में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसकी मांग की गई है, ताकि बिना किसी डर, भय के पर्व लोग मना सकें, और एकता और सद्भाव का संदेश हर



धर्म के लोग निर्भांक होकर दे सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान फा. विलियम उर्दे, भानु प्रताप सिंह, कलीम अंसारी, वसीम अंसारी, अनिल सिंह कर्नल, जितेन्द्र सिंह सोढी, आनन्द प्रकाश कुचूर, ब्लासियुस तिग्गा सहित अन्य उपस्थित थे।

कांकेर की घटना प्रदेश भाजपा सरकार की विफलता

कांकेर की घटना प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलता है। इस विफलता को छिपाने के लिए भाजपा ने चेहरा बदलकर बुधवार को अराजकता पूर्ण बंद कराया है। शहर में शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार कर रहे कई व्यापारियों ने बताया कि दुकानों को बंद कराने के लिए निकले लोगों ने अभद्रता की, जो खेदजनक है। कांग्रेस लोभ, दबाव या धोखे से धर्मांतरण के संदेह खिलाफ रही हैं। सरकार ऐसे धर्मांतरण पर रोक लगाने के बजाय अपने चेहरे बदल कर समाज में वैमनस्य फैला रही है, जो अस्वीकार है।

वालकृष्ण पाठक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेट्री, सरगुजा

अमेरा कोयला खदान के विस्तार को लेकर परसोड़ी कला में विरोध जारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के परसोड़ी कला गांव के ग्रामीणों का अमेरा कोयला खदान के विस्तार को लेकर विरोध जारी है। इसी क्रम में 24 दिसंबर को पेसा एक्ट पंचायती राज विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1996 के लागू होने की 29वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों ने स्वशासन दिवस मनाया और पेसा एक्ट और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का प्रचार-प्रसार किया। इनके द्वारा खदान विस्तार का विरोध किया गया। पेसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, जो अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अधिकार देता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय नियंत्रण, खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा शामिल है। छत्तीसगढ़ में इसे कई वर्षों बाद नियमों के साथ लागू किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन और खनन कंपनियों एसईसीएल इसे लगातार अनदेखा कर रहा है। संयोजक जनसाय पोया, तिलासो बार्ड सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि कोल बेयरिंग एक्ट 1957 का हवाला देकर अधिकारियों के द्वारा संविधान की गलत व्याख्या की जा रही है, जबकि पेसा कानून प्रमुख है। अमेरा ओपन कास्ट कोयला खदान का विस्तार हसदेव अरण्य क्षेत्र से जुड़ा है, जो जैव विविधता से भरपूर घना जंगल है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान विस्तार से उनकी जमीन, जंगल और जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही है। वे जल, जंगल, जमीन बचाओ के नारे के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान विस्तार के लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई, मुआवजा अपायस है और पर्यावरण क्षति हो रही है। वे संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही।



ट्रेक्टर की ठोकर से बाइक चालक की मौत, एक का चल रहा उपचार

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। धान लोड ट्रेक्टर की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, एक का उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जशपुर जिला के सना थाना अंतर्गत ग्राम सोहराई, कुबडुबथान निवासी लालदेव राम गिनीवार पिता सोहराई राम 22 वर्ष, मंगलवार को ग्राम कोरजकोना से बाइक में डूबोबाई को बैठाकर घर आ रहा था। ग्राम कपसेला में पुलिस के पास धान लोड ट्रेक्टर की ठोकर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जशपुर अस्पताल से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां इलाज के दौरान लालदेव राम की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

मसीही समाज के लोगों ने आतिशबाजी व केक काटकर मनाई खुशी

प्रभु यीशु के जन्म पर गिरिजाघरों में हुए विशेष धार्मिक अनुष्ठान

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मसीही समाज के लोग अपने-अपने घरों को भी रंग-बिरंगी रोशनी से सजाए थे। 24 दिसंबर को शाम होते ही काफी संख्या में समाज के महिला-पुरुष व बच्चे गिरिजाघरों में पहुंचना शुरू कर दिए थे। रात 9 बजे से अनुष्ठान शुरू हुआ। मुख्य आयोजन नावापारा गिरिजाघर में आयोजित किया गया, यहां काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। रात 12 बजते ही गिरिजाघर का घंटा बजने लगा और लोग प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने में जुट गए, आतिशबाजियां शुरू हो गईं। गिरिजाघरों सहित समाज के लोगों ने अपने-अपने घरों में केक काटा और जश्न मनाया। इसके बाद बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। मसीही समाज के लोग अपने-अपने घरों को क्रिसमस पर्व पर आकर्षक लाइट व एक्स-मस ट्री से सजाए थे। वहीं अपने-अपने घरों में भी आकर्षक चरनी तैयार किए थे। चरनी को भी आकर्षक लाइट से सजाया गया था। रात 12 बजते ही प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्य आयोजन नावापारा स्थित महागिरिजाघर में आयोजित किया गया। यहां काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। विशेष अंतोनिन बड़ा की अगुवाई में परंपरागत ढंग से विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। व्हीकल जनरल फादर विलियम उर्दे, पुरोहित फादर जार्ज ग्रे कुचूर के नेतृत्व में सारी तैयारी की गई थी। जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के अलावा मैनपाट, सीतापुर, बतौली, लुण्डा, उदयपुर, दरिमा के गिरिजाघरों में भी



क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने केक काटा और आतिशबाजी की। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। मसीही समाज के लोग पूरी रात नाचते-गाते नजर आए।

चरनी रहा आकर्षण का केंद्र नावापारा गिरिजाघर के अलावा बिशप हाउस में क्रिसमस को लेकर चरनी आकर्षक ढंग से सजाए गए थे। क्रिसमस ट्री, विशेष लाइटिंग से चरनी जगमगा रही थी। 24 दिसंबर की रात 12 बजते ही लोगों ने केक काट कर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दीं। वहीं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए गिरिजाघरों में विशेष व्यवस्था की गई थी।



Lakshmi Narayan Hospital

HEALING MATTER



डॉ. गौरव कुमार
एम.बी.बी.एस., डीएनबी (ऑर्थो)
पूर्व एमोसिफ्ट स्पेशलिस्ट (टाटा मेन हॉस्पिटल)
हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ



डॉ. आयुषी अग्रवाल
एम.बी.बी.एस (ऑनर्स गोल्व मेडल)
एमएस (गोल्व मेडिसी), डीएनबी
स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ

लक्ष्मी नारायण अस्पताल

समय : प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक

9, गुरु चौक, संगम गली, अम्बिकापुर (छ.ग.) ☎ 8305960517, 8251071106, 07774-356715

क्रिसमस एवं नववर्ष की

हादिक बधाई एवं शुभाकामनाएं...





डॉ. अजय तिकारी
पूर्व महापौर
नगर पालिक निगम अम्बिकापुर

क्रिसमस एवं नववर्ष की

हादिक बधाई एवं शुभाकामनाएं...





अरूण मिश्र



अतुल कुचूर



अश्विन कुचूर

अरूण ब्रिक्स इंडस्ट्रिज
सवराई रघुनाथपुर, सरगुजा (छ.ग.)

गणित दिवस पर मैथेमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी थीम पर हुआ 4 दिवसीय शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राष्ट्रीय गणित दिवस पर यहां के रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय में 16, 17, 19 एवं 22 दिसंबर को चार दिवसीय शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान परिषद रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान परिषद, डी. एस.टी., भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गणित में दिए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने तथा विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, उनकी



ताकिक एवं विक्षेपात्मक सोच को विकसित करना तथा गणित को कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़कर सरल एवं रोचक रूप में प्रस्तुत करना रहा। आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एच. एन. दुबे के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में किया गया। उद्घाटन

अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में डॉ. दुबे ने कहा कि गणित केवल संख्याओं और सूत्रों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात क्षमता, अनुशासन और समस्या समाधान की नींव रखता है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नवाचार,

कल्पनाशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता उज्वल विशाल ने मैथेमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी विषय पर प्रभावशाली व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने गणित और कला के अंतर्संबंधों को उदाहरणों के

माध्यम से स्पष्ट करते हुए बताया कि गणितीय संरचनाएँ किस प्रकार चित्रकला, वास्तुकला, संगीत एवं डिजाइन में सौंदर्य और संतुलन उत्पन्न करती हैं। चार दिवसीय आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए गणितीय मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शनी, गणित क्विज, भाषण प्रतियोगिता, गणितीय पहलियाँ तथा विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किए गए। इन गतिविधियों में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी सृजनात्मक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गणितीय रंगोली एवं मॉडल प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के संचालन एवं समन्वय टी. आर. राहगडाले की महत्वपूर्ण भूमिका

रही। इस अवसर पर गणित के सहायक प्राध्यापक दीपचंद एक्का एवं भौतिकी के सहायक प्राध्यापक अनिल कुमार चक्रधारी सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण ने सक्रिय सहभागिता निभाई और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में अतिथि प्राध्यापक, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। समापन दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन ने विद्यार्थियों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ रचनात्मकता एवं नवाचार को भी नई दिशा प्रदान की।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 15 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीयन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार सरगुजा जिला में संचालित समस्त शा.सा.की.थ./अशा.सा.की.थ. महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनके लिए शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के

पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा 2025-26 में विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन/पंजीयन हेतु नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक है। डाफ्ट प्रोजेक्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026 तक, संकशन लॉक करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2026 तक, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तक एवं छात्रवृत्ति भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के पश्चात सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

प्रशासन गांव की ओर अभियान समाधान शिविर में 179 हितवाही हुए लाभान्वित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। जिले के उदयपुर जनपद पंचायत में विकासखंड स्तरीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 179 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिसमें राजस्व विभाग से 38, विद्युत विभाग से 35, कृषि



विभाग से 27, पशुपालन विभाग से 12, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 9 तथा मछली पालन विभाग से 8 हितग्राही लाभान्वित हुए। शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं, महिलाओं एवं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर

दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जानकारी साझा की गई। साथ ही शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को मिशन से संबंधित कंडिका (सूचनात्मक सामग्री) का वितरण भी किया गया, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आमजन को योजनाओं की सही जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें।

हरित समृद्धि की ओर मजबूत कदम, उद्यानिकी प्रशिक्षण से सशक्त होंगे किसान और युवा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में दूरदर्शी पहल की गई है। जिला खनिज न्यास डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग से जिले के किसानों एवं स्थानीय युवक युवतियों को उद्यानिकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुशासन सप्ताह पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो भविष्य में जिले की उद्यानिकी को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप एवं कलेक्टर एस. जयवर्धन के



निर्देशन में जिले में ग्राफ्टेड टमाटर, बैंगन एवं अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़े हुए ग्राफ्टेड सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे सब्जियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में किसानों को नई ताकत मिलेगी।

अब तक जिले के किसानों को ग्राफ्टेड पौधों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय, लागत और उपलब्धता की समस्याएं सामने आती थीं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में ही ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने के लिए कौशल विकास आधारित माली प्रशिक्षण योजना लागू की है, जिससे किसानों की बाहरी निर्भरता

कम होगी। इस उद्देश्य से कलेक्टर जयवर्धन द्वारा डीएमएफ निधि से उद्यानिकी विभाग को माली प्रशिक्षण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत जिले की दो प्रमुख शासकीय उद्यान रोपणियां विकासखंड सूरजपुर के दत्तमा और विकासखंड प्रतापपुर के खोरमा उद्यान में 30-30 कुल 60 हितग्राहियों को नि:शुल्क माली प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को कटिंग, बंडिंग एवं ग्राफ्टिंग द्वारा पौधा तैयार करने की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात

उद्यानिकी टूल-किट भी प्रदान की जाएगी, ताकि प्रशिक्षित हितग्राही तुरंत अपने कार्य की शुरुआत कर सकें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में रोजगार सृजन, उत्पादन वृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही ग्राफ्टेड पौधों की सुलभ उपलब्धता, लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार और उद्यानिकी उत्पादन में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

ग्राम गौरवपथ योजना के तहत विधायक भूलन ने किया सड़क निर्माण का भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी की पहल पर ग्राम तेलईकछार, पटना एवं केदरई में सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है, उक्त निर्माण कार्य का विधायक श्री मरावी ने भूमि पूजन किया। इसी तरह ग्राम पंचायत पटना में योजना के तहत तीन प्रमुख सीसी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसमें हरपारा से आंगनबाड़ी



केन्द्र तक 500 मीटर लंबी सीसी सड़क एवं नाली का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 39.83 लाख है। वहीं खुटनपारा मार्ग में 500 मीटर लंबी सीसी सड़क एवं नाली का निर्माण 39.83 लाख, भूरीपारा में बिछिया बांध से स्कूल होते हुए तिराहा तक 500 मीटर लंबी सीसी सड़क एवं

नाली का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी लागत 37.48 लाख है। इन सड़कों के निर्माण से पंचायत के विभिन्न टोलों की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसी कड़ी में ग्राम केदरई में चारपारा मंदिर से नदी तक 500 मीटर लंबी सीसी सड़क सह नाली

का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 40.23 लाख है। इस मार्ग के बनने से धार्मिक स्थलों एवं नदी किनारे बसे ग्रामीणों को आने-जाने में सहूलियत होगी। ग्राम तेलईकछार में विशम्भर घर से खसपारा तक 1 हजार मीटर लंबी सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसकी लागत 76.86 लाख है। यह सड़क गांव की प्रमुख मार्गों से जुड़कर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। पटना पंचायत में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक के साथ रामानुजगर मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजलाल राजवाड़े, विधायक

प्रतिनिधि संत साहू, धनवीर, नीरज कुमार गुप्ता, पवन साहू, पंचायत पदाधिकारी, पूर्व सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने की अपेक्षा व्यक्त की गई। इस अवसर पर विधायक श्री मरावी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों और नालियों का निर्माण विकास की बुनियाद है। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंच भी आसान बनेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।

30 नए आरक्षकों को एसएसपी ने दिया नियुक्ति प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस विभाग में नवनि्युक्त 30 आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टर एस. जयवर्धन की मौजूदगी में एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर सभी को नियुक्ति आदेश एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। इन नव आरक्षकों की भर्ती आरक्षक संवर्ग वर्ष 2023-24 के तहत हुई है। अभ्यर्थियों ने जिला पुलिस बल सूरजपुर में आरक्षक जीडी के पद पर च्वाइनिंग दर्ज कराई। इस अवसर पर कलेक्टर व एसएसपी ने नव आरक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए



कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ उत्कृष्ट कार्य करने का संदेश दिया। नव नियुक्त आरक्षकों में मोहन कुमार, संजय पैकरा, संदीप सिंह, फलेश्वर राजवाड़े, संगीता मार्को, राजकुमार, भुवनकांत रायल, पुनिता सिरदार, चंदा, विवेक कुमार गुप्ता, नम्रता कुशवाहा,

सुपमा, गायत्री राजवाड़े, सोहन सिंह, सुरेन्द्र कुमार पैकरा, देवेन्द्र कुमार, राना सिंह, पूर्णिमा, बगर साव, छाया पैकरा, त्रिनेश्वर सिंह, दामोदर सिंह, अरूण कुमार सिंह, नर्मदा सिंह, रवि सिंह, अजय कुमार पैकरा, सुनिता सिंह, अविनाश कुमार, शोभा एवं लता भारती शामिल हैं।

सड़क हादसे में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत, परिजनों से मिले विधायक, जताई संवेदना

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विगत दिनों इलाज के लिए बिलासपुर जाते समय एनएच 130 पर तानाखार के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में शहर के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में परिवार के दो सदस्य गम्भीर रूप से आहत हैं जिनका उपचार रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की जानकारी मिलने पर मंगलवार को क्षेत्र के विधायक भूलन सिंह मरावी मृतकों के परिजनों से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। जहाँ उन्होंने मृतकों के शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार को ढाढस बंधाया और इस हादसे में गंभीर



रूप से दोनों आहतों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विधायक मरावी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे स्वयं रायपुर जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे और अपने स्तर पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान विधायक के साथ भाजपा जिला महामंत्री शिशुकांत गर्ग सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने

भी गहरा शोक व्यक्त किया। ज्ञात हो कि बीते शनिवार की सुबह शहर के मस्जिदपारा निवासी युवक 34 वर्षीय अजहर शेख उर्फ जुगनू, 26 वर्षीय तौकीर उनकी माँ 48 वर्षीय शबाना शेख, 37 वर्षीय शेख अब्दुल्ला उर्फ पंकज एवं उनकी पत्नी 33 वर्षीया साबिया शेख अल्टो कार से इलाज के लिए बिलासपुर जा रहे थे। इस दौरान घने कोहरे के कारण कटघोरा थाना

क्षेत्र के ग्राम तानाखार के पास उनकी कार सामने से आ रहे टैंकर से जा टकराई। इस भीषण हादसे में अजहर शेख उर्फ जुगनू की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अपोलो अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया। जहाँ इलाज के दौरान तौकीर की मौत हो गई एवं रायपुर ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी माँ शबाना शेख ने भी धम तोड़ दिया। इस हादसे में गम्भीर रूप से आहत शेख अब्दुल्ला उर्फ पंकज और उनकी पत्नी साबिया शेख का रायपुर में इलाज चल रहा है। बताया गया है कि मृतक तौकीर की अगले माह शादी होने वाली थी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था, जो इस हादसे के बाद गहरे मातम में बदल गया।

किसानों के उत्थान हेतु भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता जरूरी ब्रह्माकुमारी विद्या

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। ग्राम असकला में राष्ट्रीय किसान दिवस एवं नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी ने कहा कि किसानों को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है और वे देश की आबादी का 70% हिस्सा हैं। उन्होंने नशे के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि नकारात्मक भावनाएं और खान-पान विशेष नशे के कारण व्यसन पूरे प्राकृतिक वातावरण को शोषित कर रहा है। ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी ने नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया और कहा कि हमें भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाना होगा। उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा प्रकृति को सकाश एवं धन्यवाद देकर शांति का वाइब्रेशन फैलाने की बात कही। ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी ने आध्यात्मिकता के महत्व पर और देते हुए कहा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमें आत्माओं का



पिता होने के कारण आपसी संबंध में भाई-भाई हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव ने युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए दीदी से निवेदन किया और कहा कि महिलाएं, बहनें भी जागरूक हों तो नशा मुक्त में सहयोग मिलेगा। हलीम फिरदौसी ने बताया कि लुण्डा क्षेत्र नशे की जाल में फंसा हुआ है और लोगों को नशे से बचने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। अजय तिवारी ने भी किसानों के प्रति अपने विचार व्यक्त किया कि जब ध्यान करेंगे तो ज्ञान के साथ विवेक जागेगा किसी का सर झुके एसा नशा नहीं करना है बल्कि अच्छे काम का, सेवा का नशा, अच्छा कृषि का नशा, संपन्न योगी का नशा

26 को होगी रेडक्रॉस सोसाइटी प्रबंध समिति की बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी प्रबंध समिति की बैठक 26 दिसंबर को कलेक्टर एस जयवर्धन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। जिसमें सदस्यता अभियान, वार्षिक बजट आय व्यय एवं ऑडिट, बाढ़ अतिवृष्टि जल भराव में राहत, प्रारंभिक सहायता प्रशिक्षण, जूनियर रेड क्रॉस के अंतर्गत जिले के समस्त शालाओं में पंजीयन, वित्त समिति, जूनियर रेड क्रॉस उप समिति, युथ रेड क्रॉस उप समिति, स्वास्थ्य समिति आदि प्रबंधन समिति के अतिरिक्त प्रबंध समिति स्थानीय स्तर पर समिति का गठन करना उचित हो इन सब पर चर्चा किया जाएगा। इस बैठक के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल, वाइस चेयरमैन ओमकार पांडे, ब्रजज जैन, अशोक कुमार अग्रवाल एवं जिले के सभी प्रबंधन समितियों के सदस्य शामिल रहेंगे।

सम्पादकीय

सभी को नए अवसर देगी न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड डील

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कारोबारियों से लेकर किसानों और छोटे उद्यमियों यानी एएमएसएमई तक को लाभ पहुंचाएगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सांझा अवसर बढ़ेंगे। इस नई ट्रेड डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत में आने वाले करीब 95 फीसदी उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क को या तो हटा दिया जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा, जिससे व्यापार को प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। दोनों देशों का लक्ष्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इससे अर्थव्यवस्था को स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि मिल सकेगी। वहीं, न्यूजीलैंड ने भारत में निवेश बढ़ाने का भरोसा जताया है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, इससे स्थानीय उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा। यह व्यापार समझौता मार्च 2025 में तब शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए थे। दोनों देशों ने इस समझौते को अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। अब उम्मीद की जा रही है कि यह समझौता आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाएगा, बाजारों तक पहुंच आसान करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। इससे नए आविष्कार करने वालों, कारोबारियों, किसानों, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कई सेक्टर में अवसर पैदा होंगे। साथ ही छात्रों और युवाओं को भी मौके मिलेंगे। यह डील लागू होने के बाद न्यूजीलैंड को भारतीय सामानों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह कारगर मजदूरों, कारीगरों, महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही कपड़ा, ऊन, परिधान, चमड़ा और जूते जैसे उद्योगों को मौके देगा। इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, दवाइयां और रसायन जैसे उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। इस डील का मॉडल यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (इंफ्टीए) जैसा ही होगा। इस प्रस्तावित निवेश से मेन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, इनोवेशन और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत के निवेश परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। यह समझौता खेती-किसानों पर भी खास ध्यान देता है। भारतीय किसानों को न्यूजीलैंड के बाजार में फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले, अनाज और प्रोसेस्ड फूड जैसे उत्पादों को बेचने के बेहतर मौके मिलेंगे। 'एग्रिकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप' (कृषि उत्पादकता साझेदारी), 'सेटर्स ऑफ़ एक्सिलेंस' (उत्कृष्टता केंद्र) और न्यूजीलैंड की उन्नत कृषि तकनीकों तक पहुंच जैसी पहलों से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, गुणवत्ता सुधरेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत-न्यूजीलैंड के बीच माल का व्यापार 1.3 अरब डॉलर था। वहीं, 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 2.4 अरब डॉलर था, जिसमें अकेले सेवाओं का व्यापार 1.2 अरब डॉलर था। बता दें कि पिछले 5 साल में भारत की यह 7वीं फ्री ट्रेड डील है। इससे पहले 2021 में मॉरीशस, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में यूएई, 2024-25 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (इंफ्टीए), 2025 में ब्रिटेन व ओमान व अब न्यूजीलैंड के साथ डील हुई है। इससे भारत की ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप मजबूत हुई है और देश के विकास को और बेहतर मौके मिलेंगे।



योजना
डॉ. अरश्विनी महाजन

संसद में मनरेगा को विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक, 2025 (वीबी-जी राम जी) के नाम से पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद अब यह विधेयक मनरेगा का स्थान लेगा। जहां सरकार नए विधेयक को विकसित भारत के लिए सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर राजनीति कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि इस विधेयक को विस्तार से समझा जाए कि वास्तव में इसके प्रावधान क्या हैं और इससे देश और ग्रामीण भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? 2005 में बनाए गए इस अधिनियम के पीछे सोच यह थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेरोजगारी के कारण गरीबी से बचाने के लिए उन्हें आमदनी की गारंटी हो, लेकिन इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों जैसे जल संरक्षण परियोजनाएं, सिंचाई नहरें, ग्रामीण सड़कें, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं और भूमि विकास से जुड़े कार्य भी किए जा सकें। इस योजना में वित्तीयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। समझना होगा कि यह योजना रोजगार की मांग से चर्चती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सालों में जहां इस योजना में मजदूरों की दर बढ़ाकर उसे आकर्षक बनाया गया है, लेकिन रोजगार के लिए पंजीकृत करने हेतु दिससों में भारी कमी आई है। इसका अभिप्राय है कि ग्रामीण लोगों को अन्य स्रोतों से अतिरिक्त रोजगार मिलने लगा है जो मनरेगा से अछूता है। 2005 से अभी तक देश में बहुत बदलाव आ चुका है, ऐसे में सरकार का मानना है कि मनरेगा कानून में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की

समय की जरूरत रोजगार गारंटी कानून

नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक अधिकार-आधारित योजना है, जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 से लागू किया। इस अधिनियम के तहत, किसी भी ग्रामीण परिवार का 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का वयस्क सदस्य काम के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों तक कार्य देने की बाध्यता है और यदि लिखित या मौखिक मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता, तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। दुनिया भर में कहीं भी ऐसी रोजगार के अधिकार की कोई योजना नहीं है। सूखा, कृषि संकट और कोविड-19 जैसे झटकों के समय इसने आर्थिक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई, जब लाखों प्रवासी श्रमिक गांव लौट आए और इसी योजना पर निर्भर रहे। इस योजना में कुछ बड़े बदलाव प्रस्तावित करते हुए संसद में विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक, 2025 (वीबी-जी राम जी) पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद अब यह विधेयक मनरेगा का स्थान लेगा। जहां सरकार नए विधेयक को विकसित भारत के लिए सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर राजनीति कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि इस विधेयक को विस्तार से समझा जाए कि वास्तव में इसके प्रावधान क्या हैं और इससे देश और ग्रामीण भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? 2005 में बनाए गए इस अधिनियम के पीछे सोच यह थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेरोजगारी के कारण गरीबी से बचाने के लिए उन्हें आमदनी की गारंटी हो, लेकिन इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों जैसे जल संरक्षण परियोजनाएं, सिंचाई नहरें, ग्रामीण सड़कें, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं और भूमि विकास से जुड़े कार्य भी किए जा सकें। इस योजना में वित्तीयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। समझना होगा कि यह योजना रोजगार की मांग से चर्चती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सालों में जहां इस योजना में मजदूरों की दर बढ़ाकर उसे आकर्षक बनाया गया है, लेकिन रोजगार के लिए पंजीकृत करने हेतु दिससों में भारी कमी आई है। इसका अभिप्राय है कि ग्रामीण लोगों को अन्य स्रोतों से अतिरिक्त रोजगार मिलने लगा है जो मनरेगा से अछूता है। 2005 से अभी तक देश में बहुत बदलाव आ चुका है, ऐसे में सरकार का मानना है कि मनरेगा कानून में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की



आवश्यकता है। हालांकि विधेयक में मनरेगा में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिन तक और वनवासी क्षेत्रों में तो 150 दिनों तक रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अब उसका वित्तीयन अकेले केंद्र सरकार नहीं बल्कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का दायित्व होगा। गौरतलब है कि 2005 केंद्रीय राजस्व में राज्य सरकारों का हिस्सा मात्र 32 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो चुका है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को यही कहकर बढ़ाया था ताकि वे योजना का भार वहन कर सकें। लेकिन नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो पहले ही बन चुका था, उसमें राज्यों पर इसका भार नहीं डाला जा सकता था। हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (नरेगा) 2005 में पास हुआ था और इसे 2006 में लागू किया गया। 2009 में तब की यूपीए की सरकार ने इसका नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था, और अब जब इस योजना का नया रूप संसद ने प्रस्तावित किया है और नाम में बदलाव होना भी स्वाभाविक था, जो इंतोफाक से भगवान राम के नाम से मिलता-जुलता है। इसी बात का विपक्ष विरोध कर रहा है। मनरेगा का उद्देश्य बेरोजगारी के दिनों में आय-सुरक्षा देना था, परंतु यदि कृषि मौसम में श्रमिक मनरेगा की ओर आकर्षित रहते थे। ऐसे में खेतों में श्रमिकों की कमी के चलते मजदूरी लागत बढ़ जाती है, जिससे किसान की

लागत में वृद्धि हो जाती है और खेती की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है। इस नए विधेयक में इस समस्या का समाधान निकाला गया है और रोजगार गारंटी कार्यक्रम में खेती के लिए आवश्यक 60 दिनों में इस कार्यक्रम को स्थगित रखने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में भी समय के साथ बदलाव करते हुए अब उसमें आज की आवश्यकता के अनुरूप, जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी-रोटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब मौसम की घटनाओं को कम करने को शामिल करने के साथ-साथ, इन योजना को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ भी जोड़ा गया है। मनरेगा का सबसे बड़ा दोष यह था कि तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा था। ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण बड़ी मात्रा में सरकारी धन की लूट हो रही थी, ऐसी हुई योजनाएं ध्यान में आती थी जिसमें हे कागजों पर ही तमाम निर्माण हो जाते थे, जिनका धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। नए अधिनियम में भ्रष्टाचार को बाहर रखने के लिए प्रावधान रखा गया है कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रावधान है, जिसमें लेन-देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, योजना निर्माण एवं निगरानी के लिए भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय में निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित डैशबोर्ड तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उसमें भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगाया गया है, उसी तर्ज पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए रोजगार गारंटी योजना में भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। देश में कई विधेयकों द्वारा मनरेगा का विरोध इस लंबे व्यू से हो रहा था कि इसके चलते कृषि और उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो रही है, हालांकि कृषि में तो श्रमिकों की कमी की समस्या को कुछ हद तक नए अधिनियम में हल करने का प्रयास हुआ है, लेकिन मनरेगा के कारण उद्योगों और कृषि की सहायक गतिविधियों हेतु श्रमिकों की कमी के समाधान का की समस्या के समाधान का भी प्रयास करना जरूरी था। विपक्ष संसद में नामकरण जैसे गैर जरूरी मुद्दों को उठाने की बजाए यदि नए अधिनियम में देश की आवश्यकता के अनुरूप प्राधान्य शामिल कराने हेतु बहस करता तो मनरेगा के इस नए अवतार में कुछ और सुधार भी शामिल किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

(लेखक पूर्ण प्रोफेसर हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

बलिदान दिवस

आचार्य दीपचन्द भारद्वाज



त्याग की प्रतिमूर्ति निर्माक

संन्यासी स्वामी श्रद्धानंद

स्वामी श्रद्धानंद का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित था। इनका पूर्व नाम मुंशीराम था। 1879 में एक बार बरेली में स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रवचन हुआ। मुंशीराम के पिताजी ने इनको भी स्वामी दयानंद के उस कार्यक्रम में जाने के लिए कहा। मुंशीराम का जीवन स्वामी दयानंद के प्रवचनों तक ही सीमित नहीं था। बहुत प्रभावित हुआ। स्वामी दयानंद के उपदेशों ने नास्तिक मुंशीराम को आस्तिक बना दिया। अपने जीवन में त्याग सम्पत्त व्यसनों का परित्याग करके वर्ष 1884 में मुंशीराम जी आर्य समाज लाहौर के सदस्य बने। स्वामी दयानंद के वैदिक ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित किया। 1902 में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसी महान संस्था की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने समाज के उत्थान के लिए तथा अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नामक ऐतिहासिक संस्था की नींव रखी।

इस संस्था के माध्यम से इस निर्भीक संन्यासी ने मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती देने का कार्य किया जो उस समय पूर्णरूपेण असंभव था। सर्वप्रथम कन्याओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला तथा सबसे पहले अपने बच्चों को गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा हेतु तैयार किया। इसी गुरुकुल कांगड़ी से अनेक विद्वान, राष्ट्रभक्त, बलिदानी तैयार हुए। कल्याण मार्ग के पथिक महात्मा मुंशीराम ने त्याग के महान आदर्श का अनुसरण करते हुए अपनी जालंधर वाली कोठी तथा संपूर्ण संपत्ति आर्य समाज को दान कर दी। वर्ष 1917 में महात्मा मुंशीराम ने संन्यास ग्रहण किया तथा अपना नाम श्रद्धानंद रखा। ईश्वर में इनकी अगाध श्रद्धा थी, इसलिए इन्होंने अपना यह नाम रखवाया। 1919 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सभाओं और जलसों को पूर्ण रूप से बंद करने का अंग्रेज सरकार ने आदेश जारी किया तब स्वामी श्रद्धानंद ने चांदनी चौक टाउन हॉल के सामने आंदोलन करते हुए उन्हीं अंग्रेजों सेना के सामने सीना खोलकर गोली चलाने की चुनौती दी थी। इस निडर संन्यासी के सामने उस समय अंग्रेजों की भी नतमस्तक होना पड़ा था। जलियांवाला बाग की दमनकारी तथा क्रूर घटना के बाद पूरे पंजाब में भय और आतंक का माहौल था, ऐसे डरावने माहौल में कोई भी कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था तब इन्हीं स्वामी श्रद्धानंद ने अपने दुर्दु संकल्प के बल पर कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन संपन्न करवाया। गुरुकुल कांगड़ी का प्रबंध आचार्य रामदेव को सौंप कर स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली पहुंचे। यहाँ से उन्हीं अपनी राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया। 1922 में जब सिखों ने गुरु का वाग का सत्याग्रह शुरू किया तो अंग्रेजों ने इसे दबाने का प्रयास किया। स्वामी श्रद्धानंद को जब पता चला तो वे तुरंत अमृतसर पहुंचे और इस सत्याग्रह का संचालन अपने हाथ में लिया। स्वामी श्रद्धानंद ने शूद्र आंदोलन प्रारंभ करके मुस्लिमों के भय से धर्म परिवर्तन करने वालों को पुनः अपने धर्म में शुद्धिकरण के माध्यम से प्रवेश करवाया। सर्वप्रथम आगरा के मलकाने राजपूतों की स्वधर्म में वापसी कर्वाकर शुद्धि के इस महान आंदोलन का सूत्रपात किया। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आर्य जगत में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। स्वामी दयानंद के व्रत कथा संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया।

कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति से नाराज होकर स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। शुद्धि आंदोलन के कार्य से कुछ सांप्रदायिक लोग उनसे नाराज हो गए और 23 दिसंबर 1926 को एक मतांध सांप्रदायिक मुस्लिम ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद जीवन पर्वत राष्ट्र, धर्म, जाति तथा अपने स्वर्णिम वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु प्रयासत रहे। कल्याण मार्ग के पथिक, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद का यह आदर्शमय तथा त्यागमय जीवन संपूर्ण आर्य जाति के लिए प्रेरणा स्तंभ के समान है। स्वामी श्रद्धानंद का का जीवन पुरुषार्थ और कर्ममय था। देश और आर्य समाज के लिए स्वामी श्रद्धानंद का योगदान और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा और उन्हींने हमेशा डटकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में कसर नहीं छोड़ी। उन्हींने अतिशय क्षणी तक अपने पावन कार्यों के माध्यम से आर्य समाज की सेवा की। श्रद्धानंद जी का संपूर्ण जीवन युवा आर्य शक्ति को नई ऊर्जा, पुरुषार्थ तथा राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला है।

(लेखक अख्यारिक विक्त हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

आवश्यकता से अधिक मंथन से विष ही निकलता है

व्यक्ति को कर्मशील रहना चाहिए, मगर सहज संतुलन भी आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी अधिक व्यस्त है। उसकी इतनी व्यस्तता चिंता का कारण है। व्यस्तता का बड़ा कारण तकनीक का अधिक प्रयोग भी है। युवा चिंतन में लगे रहते हैं। कम समय में अधिक से

आधक काम करना चाहत है। समुद्र मंथन का काय त भलाइड का लए ह हा रहा था आर रल निकल रहे थे, परंतु न तो देवताओं को संतोष था और ना ही असुरों को। अधिक से अधिक रत्न निकालने की चाह में मंथन होता गया और एक समय ऐसा आया, जब विष निकलने लगा, जिसे पीने को कोई तैयार नहीं था। सब त्राहि-त्राहि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने विष को पिपा और श्रीराम का नाम लिया। युवा नई तकनीक का प्रयोग करें, खोज करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक चिंतन न करें। लगातार नई तकनीक में डूबे रहने की आदत का प्रभाव नकारात्मक होता है। आवश्यकता से अधिक मंथन से विष ही निकलता है। आज के समय में विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ और मोह तो फिर भी कुछ न कुछ अंश में सांसारिक जीवन के भाग हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इसका कुछ भाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष व निंदा का जीवन में कोई काम नहीं है। ये ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल (विष) के समान हैं। अज धर्म क्षेत्र में भी ईर्ष्या, द्वेष व निंदा का असर है जो उचित नहीं है। अगर हमें शिव की भक्ति करनी है तो इस विष का पान भी करना होगा। भगवान शिव भक्ति भी देते हैं और मुक्ति (मोक्ष) भी।



करंट अफेयर

भारतीय मूल के वरदराजन स्टारबक्स के सीटीओ बने

अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 'स्टारबक्स' ने भारतीय मूल के आनंद वरदराजन को अपना नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) नियुक्त किया है। करीब दो दशकों तक अमेजन में काम कर चुके वरदराजन को दुनियाभर में कॉफीहाउस श्रृंखला के लिए मशहूर इस कंपनी के वैश्विक प्रौद्योगिकी संचालन की कमान सौंपी गई है। स्टारबक्स के अनुसार, वरदराजन 19 जनवरी से पदभार संभालेंगे, कंपनी की कार्यकारी नेतृत्व टीम में शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन निकोल के मातहत काम करेंगे। वह डेब हॉल लेफ्टर का स्थान लेगे, जो रिस्तर में सेवानिवृत्त हुई थीं। अमेजन में अपने लगभग 19 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वरदराजन ने बड़े पैमाने पर ग्राहक-केंद्रित प्रौद्योगिकी में विकसित किए। हाल के वर्षों में वह अमेजन के 'वर्ल्डवाइड ग्रॉसरी स्टोर' कारोबार के लिए प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी 'ओरेकल' में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में और कई स्टार्टअप के साथ भी काम किया। स्टारबक्स ने कहा कि वरदराजन को सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियां विकसित करने तथा परिचालन उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करने का गहरा अनुभव है, जिसमें ग्राहकों को केंद्र में रखा जाता है।



अंतर्मन

आज की पाती

नागरिक चेतना से बचेगी प्रकृति
पर्यावरण संरक्षण की बहस अक्सर एक सुविधाजनक दिशा में मोड़ दी जाती है-सरकार नीतियां नहीं बनाती, मंत्रालय निष्क्रिय है, कानून कागजों तक सीमित है। यह आलोचना पूरी तरह गलत नहीं है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंत्रालयों का रिकॉर्ड देखे तो विकास परियोजनाओं के सामने प्रकृति अक्सर सबसे पहले बलि चढ़ती दिखती है। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, जहरीली हवा और भूजल का संकट- इन सबके लिए नीतिगत विफलता जिम्मेदार है। पर यह अशुभ संघ है। पूरा सच यह है कि पर्यावरण संकट की जड़ हमारी अपनी जीवन-शैली में गहरी छसी हुई है। हमने पर्यावरण को संरक्षक का विषय मान लिया है, जैसे वह नागरिक जीवन से अलग कोई विभागीय फाइल हो। नागरिक चेतना जरूरी है। - *जिष्णु वाटक, रायगढ़*

ऑफ बीट

जेनेटिक कोड में एक ही चीज के लिए है बहुत सारे शब्द

आनुवंशिक कोड की सार्वभौमिकता सभी जीवित जीवों के बीच एक सामान्य वंशावली को इंगित करती है और यह कोड जैविक कोशिकाओं की संरचना, कार्य और विनियमन में आवश्यक भूमिका निभाता है। यह समझना कि जेनेटिक कोड कैसे काम करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक जीव विज्ञान की नींव है। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग जैसी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए कोड क्यों महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक कोडबुक चार अक्षरों से बने 'शब्दों' से बनी है- ए, सी, जी और यू। इनमें से प्रत्येक अक्षर एक अलग रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है- एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल। राइबोसोम नामक एक आणविक मशीन जीन को प्रोटीन में अनुवाद करने के लिए कोडबुक को पढ़ती है। राइबोसोम तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ते हैं जिन्हें कोडोन कहा जाता है, और चार अक्षरों के 64 अलग-अलग संभावित संयोजन होते हैं जो अलग-अलग कोडोन बनाते हैं। 64 शब्दों की इस सूची में, 61 अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं, और तीन कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए राइबोसोम को संकेत देते हैं।



टेंड

सुशासन के लिए कटिबद्ध

विहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुखदेव चौधरी से उठे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार प्रष्टा ने जनकल्याण, विकास और सुशासन को और अधिक ऊंचाई देने के लिए कटिबद्ध है। -*अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री*

मनरेगा की संरचना खत्म

नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्वी, परमार्थ व सदीय प्रक्रियाओं तथा रेट्टे रायत खंडों के प्रति समान के निम्न मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। योजना से महकन गांधी का नाम उखाड़ा जाना तो एक बर्तनी भर है। सरकार ने मनरेगा की संरचना को नष्ट किया है। -*सोनिया गांधी, कांग्रेस सदस्यत्व एवं पूर्व प्रमुख*

अधिकारी अयोग्य

एस.आई.आर पर सुनवाई के लिए मद्राको ऑर्गेनर के तौर पर नियुक्त केटीय अधिकारियों को रक्षावर्ती भाषा (बालक) का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी रक्षावर्तन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वैरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य है। -*मनता बर्नार्जी, सीएम ए. बंगाल*

मैं निराश नहीं

विफेट नहीं मिलने से मैं निराश नहीं हू। तुझे खुशी है कि मैं रणनीति पर अडिग रहूँ। तूने अन्तल करने में सफल रही। अभी चार तैयार खेले जाने बाकी हैं। शुरू में मैं चौड़ी नदियाँ थी, लेकिन राष्ट्रवाज के बाद सहज हो गई थी। -*वैशाखी शर्मा, क्रिकेटर*



रायगढ़ में विकास योजनाओं की मैराथन समीक्षा: कृषि मंत्री ने 13 विभागों को दिए सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कृषि तथा आदिम जाति विकास मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने आज रायगढ़ कलेक्टर के कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित तेरह महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की गहन एवं बिदुवार समीक्षा की। प्रभारी मंत्री मंगलवार को जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, महापौर जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष दीपक सिदार, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित विभागीय अधिकारी एवं वरिष्ठ

प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

धान खरीदी और कृषि क्षेत्र में व्यापक निर्देश

कृषि मंत्री मंत्री श्री नेताम ने राज्य शासन की सर्वाधिक प्राथमिकता में शामिल धान खरीदी योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि वास्तविक किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भुगतान समयबद्ध करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले से लगे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं एवं प्रमुख मार्गों पर धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि रायगढ़ जिले की जलवायु बहु आयामी एवं नकदी फसलों

के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने किसानों को उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए टोस कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मखाना की खेती को जिले में संभावनाशील बताते हुए इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने पर जोर दिया। साथ ही कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र को संयुक्त रूप से तिल एवं अरहर की खेती को बढ़ावा देने हेतु वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजनाएं बनाने के निर्देश दिए।

पशुधन, मत्स्य और वनांचल आधारित आजीविका पर जोर

पशुधन विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कुक्कुट पालन, बकरी पालन एवं मत्स्य पालन को किसानों की आय वृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने इन योजनाओं से अधिक



से अधिक किसानों को जोड़ने, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वनांचल क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से सुकर पालन को उनकी रुचि के अनुसार प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

व्यवस्थापक संरक्षण और जनजागरूकता पर विशेष निर्देश

प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों के अवैध शिकार, विशेषकर बिजली करंट जैसे

खतरनाक साधनों के उपयोग से होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल वन्यजीवों के लिए घातक हैं, बल्कि कई बार जनहानि का कारण बनकर पीड़ित परिवारों को वर्षों पीछे धकेल देती हैं। उन्होंने वन विभाग, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को मिलकर जनजागरूकता अभियान चलाने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों को समझाया देने तथा सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने कुपोषण की दर में प्रभावी कमी लाने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं

के सुदृढ़ क्रियान्वयन, पोषण आहार की गुणवत्ता एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं एवं छात्र उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री जनमन, आवास और सूर्य घर योजना पर फोकस

आदिमजाति विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन एवं आवास निर्माण कार्यों में तेज प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को उच्च गुणवत्ता

एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में इसके विस्तार एवं क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए। और कहा कि आने वाले समय में यह योजना ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता साबित होगी। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल रेडी-टू-ईट निर्माण हेतु जिले में प्रस्तावित दस मध्यम उद्योगों की स्थापना की जानकारी ली और सुचारु रूप से उत्पादन में आ रही अड़चनों को दूर कर निर्धारित मानक गुणवत्ता के साथ उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिजली विभाग, लोक सेवा गारंटी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री श्री साय



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यहां राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के

लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेले इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं।

सुशासन, संवेदना और सुरक्षा : श्रमिक हित में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पॉकेट में खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की संकल्पबद्ध प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग विगत दो वर्षों में इसी सुशासन की भावना को धरातल पर साकार करता हुआ दिखाई देता है। इस अवधि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने तथा उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेक ऐतिहासिक और जनहितकारी

कदम उठाए गए हैं। विष्णु के सुशासन की स्पष्ट झलक श्रम विभाग द्वारा अपनाए गए डिजिटल नवाचारों में दिखाई देती हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त नस्त्रियों का संधारण ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। विभागीय योजनाओं और सेवाओं को आमजन के लिए सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु एक आधुनिक, सूजर-फ्रेंडली विभागीय वेबसाइट विकसित की गई है। श्रमिकों की सुविधा को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया ह्यश्रमवैजयते मोबाइल ऐप श्रमिक पंजीयन, योजनाओं में आवेदन तथा श्रमिक पलायन की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा

है, जो डिजिटल सुशासन की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। राज्य के नवगठित जिलों तक श्रम विभाग की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाँच नवीन श्रम पदाधिकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के दौरान श्रमायुक्त संगठन अंतर्गत श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पदों पर कुल 32 नई नियुक्तियाँ की गईं। इन प्रयासों से न केवल विभागीय कार्यों में गति आई, बल्कि श्रमिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ भी सुनिश्चित हुईं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में आवश्यक और संतुलित सुधार करते हुए ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और श्रमिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित

किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन से छोटे व्यापारियों को राहत मिली, वहीं नियत कालिक नियोजन कर्मकार की नई श्रेणी ने रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोले। राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत लागू किए गए छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन एवं विविध प्रावधान विधेयक, 2025 के माध्यम से अवैधानिक हड़ताल पर नियंत्रण, छोटे अंतरालों में समझौते तथा लघु उद्योगों को ब्यूट जैसे प्रावधान किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों के सशर्त नियोजन की अनुमति देना सरकार की प्रगतिशील और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन

में श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की मानवीय प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। विभिन्न श्रम मंडलों के माध्यम से दो वर्षों में 11,03 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा 27.33 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस अवधि में 784.73 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिक कल्याण पर व्यय की गई, जो यह दर्शाता है कि यह सरकार आंकड़ों से आगे बढ़कर संवेदना के साथ श्रमिकों के जीवन में बदलाव ला रही है। 247 संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र ने शिकायत निवारण और पंजीयन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया है। वहीं प्रत्येक जिले और विकासखंड में संचालित मुख्यमंत्री श्रम

संसाधन केंद्रों ने प्रशासन को सचमुच श्रमिकों के द्वार तक पहुँचाया है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की व्यवस्था ने प्रक्रियाओं को सरल किया, जबकि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के माध्यम से सैकड़ों श्रमिक परिवारों को अपने पक्के आवास का सपना साकार करने में सहायता मिली। मिनीमाता महतारी जतन योजना एवं असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के अंतर्गत लाखों महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता प्रदान की गई, जिससे मातृत्व सुरक्षा को नया संबल मिला। श्रमिक परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

किसानों की सुविधाओं और मंडी अधोसंरचना को मिलेगा नया आयाम: कृषि मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले में कृषि एवं मंडी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कृषि मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम ने आज कृषि उपज मंडी समिति पटेलपाली रायगढ़ में 6.15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भूमिपूजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व



में राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में जनदेश परब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत की गई घोषणाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारा जा रहा है।

आज जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया है, उनसे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा, सुगम आवागमन और आधुनिक मंडी अधोसंरचना उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उपज के प्रबंधन और विपणन में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, किसानों को उपज के भंडारण एवं विक्रय में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी।

रायगढ़ को नई पहचान मिल रही: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से रायगढ़ जिले में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंडी क्षेत्र में हुए विकास को किसान और व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के नेतृत्व में मंडियों का विकास किसानों के लिए मील का पथर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत कृषि अधोसंरचना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और किसान सशक्त होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जय जवान-जय किसान का नारा दिया। कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 15 हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक

का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषक प्रतिनिधि आमोद नायक एवं माधव साव द्वारा प्रभारी मंत्री को जैविक जवाफूल चावल भेंट किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्रीलाल साहू, जनपद पंचायत पुसौर अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान, अरुण धर दीवान, अभिषेक शुक्ला, उमेश अग्रवाल, विकास केडिया, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज खिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए खेले इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 के शुभंकर हामोर वीर, थीम सॉन एवं खेले इंडिया टॉच का रिमोट बटन दबाकर अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। उद्घाटन समारोह में अल्लुमाडू क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा मलखंब को उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई। महिला कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी



एवं एथलेटिक्स खिलाड़ी अमित कुमार द्वारा खेले इंडिया टॉच का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं। राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह युवा महोत्सव न केवल युवाओं की प्रतिभाओं को पहचान देने का मंच है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय

स्तर तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खेले इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने, मलखंब खिलाड़ियों को एक लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान करने तथा अमेरिका गॉट टैलेंट में चयनित मलखंब खिलाड़ी अनरटॉपीटाई के अमेरिका आने-जाने का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ में कौशल-एकीकृत औद्योगिक विकास को मिल रही नई गति - विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भविष्य-उन्मुख कौशल विकास के साथ औद्योगिक विकास को सुदृढ़ रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। यह उद्योग-केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना (पीएम सेतु) के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

गेल का 10,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना प्रमुख आकर्षण

इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न



निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए तथा निवेश आभ्रमण पत्र जारी किए गए। कुल मिलाकर 13,690 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश सामने आए हैं, जिससे राज्य में 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार को मजबूती प्रदान करेंगे।

कौशल-आधारित औद्योगिक विकास की धुरी बना गेल का प्रोजेक्ट

निवेश प्रतिबद्धताओं में गेल का

प्रस्तावित गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र राज्य के लिए एक प्रमुख एवं सबसे बड़े औद्योगिक प्रस्तावों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया। लगभग 10,500 करोड़ रुपये के प्रथम चरण निवेश तथा 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) यूरीया उत्पादन क्षमता के साथ यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल एवं उर्वरक मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करेगी। यह प्रस्तावित परियोजना गेल की मुंबई-नागपुर-झारखण्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) के साथ प्लान की गई है।

कैबिनेट मंत्री ने खैरबार और जुनाडीह में बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के संकल्प के साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के खैरबार में समूह जल प्रदाय योजना और लखनपुर विकासखंड के जुनाडीह में 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 4604.12 लाख रुपये की लागत से खैरबार में होने वाले बहुप्रतीक्षित समूह जल प्रदाय योजना से अम्बिकापुर क्षेत्र के 32 ग्रामों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल

समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।

4604.12 लाख की समूह जल प्रदाय योजना से 32 ग्रामों को शुद्ध पेयजल

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव इस सुविधा से वंचित न रहे। समूह जल प्रदाय योजना के पूर्ण होने पर इन 32 ग्रामों की बड़ी आबादी को हैडपंप और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही जलजनित बीमारियों में भी कमी आएगी। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण



सहयोग देते हुए जल संरचनाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा में भी भागीदार बनें। लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम जुनाडीह में 1.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास का भूमिपूजन करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के बिना समग्र विकास संभव नहीं

है। यह छात्रावास दूरस्थ आदिवासी इलाकों के मेधावी और इच्छुक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें शहरों तक बार-बार आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा के

बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा केवल संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। छात्रावास के संचालित हो जाने पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास गति पकड़ेगा। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संकल्प है कि सरकार की योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें और हर गाँव को मूलभूत सुविधाओं से सशक्त बनाया जाए। स्वच्छ जैसी बुनियादी जरूरतों के प्रति वे परियोजनाएँ उसी प्रतिबद्धता की कड़ी हैं।

सुशासन सप्ताह: तहसील प्रतापपुर में आवेदक को मिली नकल की कॉपी



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। सुशासन सप्ताह - सुशासन गांव की ओर अभियान के तहत तहसील कार्यालय प्रतापपुर में प्राप्त नकल आवेदन का त्वरित निस्तारण कर आवेदकों को नकल प्रदान की गई। सुशासन सप्ताह के दौरान तहसील कार्यालय द्वारा जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए लंबित नकल आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। तहसील कार्यालय में प्राप्त समस्त नकल आवेदनों की जांच कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है और आवेदकों को नकल उपलब्ध कराई जा रही है। नकल प्राप्त करने वाले आवेदक ने प्रशासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुशासन सप्ताह के दौरान मिली इस त्वरित सेवा से उनका काफी समय बचा और उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ी।

26 दिसंबर को कलेक्टर सभा कक्ष में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी प्रबंध समिति बैठक का होगा आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा 26 दिसंबर को कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के अध्यक्षता में प्रबंध समिति का बैठक रखा गया है। जिसमें सदस्यता अभियान पर चर्चा, वार्षिक बजट आय व्यय एवं ऑडिट पर चर्चा, बाढ़ अतिवृष्टि जल भराव में राहत पर चर्चा प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण पर चर्चा, जूनियर रेड क्रॉस के अंतर्गत जिले के समस्त शालाओं में पंजीयन पर चर्चा, वित्त समिति, जूनियर रेड क्रॉस

आवास चौपाल के माध्यम से कलेक्टर ने पीएम आवास हितग्राहियों की सुनी समस्याएं

0 बेहतर आवास बनाने पर हितग्राहियों को किया गया सम्मानित 0 निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूर्ण करने की अपील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। शासन के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रगति की निरंतर समीक्षा राज्य कार्यालय से की जा रही है। कलेक्टर एस जयवर्धन एवं सीईओ जिला पंचायत विजेन्द्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन एवं निर्देशों में जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में आवास चौपाल के माध्यम से हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित किए जाने का कार्य किया जा रहा है।

सुशासन सप्ताह के तहत जिले में अब तक 350 से अधिक जगहों पर आवास चौपाल आयोजित कर लगभग 10 हजार हितग्राहियों से समन्वय स्थापित किया जा चुका है। इसी अनुक्रम में बुधवार को कलेक्टर श्री जयवर्धन की अध्यक्षता में जनपद पंचायत भैयाथान के ग्राम बंजा में सेक्टर बनाकर

आवास चौपाल आयोजित किया गया। उक्त चौपाल में हितग्राहियों से वन टू वन चर्चा कर आवास नहीं बनाने के कारणों से अवगत हुए। सेक्टर



में उपस्थित संबंधित ग्राम पंचायत बंजा, सोनपुर शि, खड़गवा, जूर, शिवप्रसादनगर, कुसमुसी एवं भंवरारी के सरपंचों ने पीएम आवास निर्माण में अपनी भूमिका के बारे में संक्षेप में बताया। कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास के निर्माण की निगरानी

राज्य कार्यालय से निरंतर हो रही है। शासन आपसे अपील करता है कि आपको अगर आवास की स्वीकृति मिली है तो आप बिना विलंब किए,



रहे हैं, वहां पर प्रतीक्षा सूची से नाम जल्दी आ रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेन्द्र सिंह पाटले ने कहा कि सेक्टर में विगत 2 वर्षों के कार्य को देखे तो 325 हितग्राहियों के आवास पूर्ण होने लंबित है इन हितग्राहियों को जल्द आवास पूर्ण करना चाहिए, ताकि हाल में सर्वे हुए सूची से नामों को स्वीकृति प्रदान की जा सके।

चौपाल में उपस्थित हितग्राहियों में से 6 माह के भीतर अच्छा और जल्दी आवास पूर्ण करने

वाले शिवप्रसादनगर के शिवधारी, शंकर, भंवरारी के श्रीमती बेलसिया इंद्रपाल एवं बंजा के घनश्याम कलेश्वर को उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही घनश्याम के आवास पर जाकर विधिवत पूजा पाठ करते हुए, आवास में गृह प्रवेश कराया गया।

मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नए डीआरएम से की मुलाकात

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन विश्रामपुर। साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के मण्डल समन्वयक विजय अग्निहोत्री

जोनल कोषाध्यक्ष साई किरण चंदू एवं डीआरएम कार्यालय ब्रांच सचिव राणा नंदी के साथ बिलासपुर मण्डल के नवपदस्थ मण्डल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के बिलासपुर डीआरएम पद पर पदभार संभालने पर मजदूर कांग्रेस की ओर से स्वागत कर शुभकामनाएं बधाई दी।

रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव ने बताया कि इस बैठक में अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक तथा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी डॉ. अशुभ मिश्रा भी मौजूद थे। भेंट में कर्मचारियों से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यतः मेडिकल विभाग से संबंधित विषय जैसे कोरबा, बृजराजनगर एवं उमरिया में मेडिकल सुविधा ना होने के कारण अन्य निजी अस्पतालों

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

के साथ टाईअप करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेक मेंटेनर के पदोन्नति एवं

मंत्री लक्ष्मी व विधायक भूलन के प्रयास से ओड़गी-बिश्नुपुर सड़क हेतु मिली 32 करोड़ की स्वीकृति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। ओड़गी से बिश्नुपुर तक लोक निर्माण विभाग की सड़क के मजबूतीकरण का सपना अब साकार होने जा रहा है। लगभग 32 किलोमीटर

लक्ष्मी राजवाड़े एवं प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री एवं विधायक के

पड़ता था। अब सड़क मजबूतीकरण के बाद आवागमन सुगम होगा, समय की बचत होगी और दुर्घटनाओं



में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क न सिर्फ यातायात सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को भी नई गति देगी। ग्रामीणों ने भी सड़क निर्माण की स्वीकृति पर जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे लंबे समय से चली आ रही मांग का पूरा होना बताया।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने जताया आभार

लंबी इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण एवं सुदृढीकरण के लिए 32 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री

लगातार प्रयास, सतत पत्राचार और गंभीर पहल के कारण ही यह बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजना स्वीकृत हो सकी है। जिलाध्यक्ष श्री सोनी ने कहा कि ओड़गी-बिश्नुपुर मार्ग क्षेत्र के लिए जीवनरेखा समान है। सड़क जर्जर होने के कारण ग्रामीणों, मरीजों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता था। अब सड़क मजबूतीकरण के बाद आवागमन सुगम होगा, समय की बचत होगी और दुर्घटनाओं

कांकेर की घटना एवं धर्मांतरण के विरोध में बंद रहा शहर, हुई जनसभा, निकली आक्रोश रैली

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। कांकेर जिला के आमाबेड़ा-बडेतेबड़ा में जनजातीय समाज के ऊपर हिंसक हमला एवं धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को शहर बंद रहा। अग्रसेन चौक में सर्व

आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में दबाव, प्रलोभन या गलत जानकारी के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिस पर प्रशासन एवं कलेक्टर को सख्ती से कार्रवाई करनी

स्थान दिया गया, राजवाड़े समाज से सुश्री शशि राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण घर-घर में गांव-गांव में अराजकता फैल रही है और अपने ही परंपरा के दुश्मन होते जा रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ टोस कानून की आवश्यकता है अंत में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन का वाचन दिनेश साहू के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में अनेकों समाज के प्रमुख शामिल थे।

सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

समाज के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया तत्पश्चात शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के तत्वावधान में आक्रोश रैली निकाली गई। इस आंदोलन का व्यापारियों ने भी पूर्णतः नगर में साथ दिया और नगर बंद का असर पूर्णता देखने को मिला। समाज के लोगों ने



खुलकर विरोध करता है यह सीधा-सीधा हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। साहू समाज से अनुज साहू ने अपने वक्तव्य में कहा कि वहां के संबंध पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार अन्य अधिकारी ने निष्ठा पूर्वक कांकेर घटना को लेकर निष्पक्ष पहल नहीं किया पीडित जनजातीय समाज पर ही कार्यवाही की यह अत्यंत घोर निंदनीय है, ब्राह्मण समाज से

चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कानून का कड़ाई से पालन, जांच की पारदर्शी प्रक्रिया, और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग रखी। प्रशासन की ओर से ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। मंच पर सभी समाजों के प्रमुखों को ससम्मान

मनोज पांडेय ने कांकेर जिले की घटना का निष्पक्ष से जांच बैठानी चाहिए और अराजक फैला रहे और सामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए एवं जनजातीय समाज के संभाग प्रमुख बाबूलाल मोयपो ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा की विस्तृत जानकारी दी, और अपने वक्तव्य में ईसाई मिशनरियों और भीम आर्मी के संयुक्त षड्यंत्र जो जनजातीय समाज पर हमला देखने को मिला यह जनजातीय समाज की सीधा परंपरा आस्था को ठेस पहुंचाया है। धर्मांतरण के कारण घर-घर में गांव-गांव में अराजकता फैल रही है और अपने ही परंपरा के दुश्मन होते जा रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ टोस कानून की आवश्यकता है अंत में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन का वाचन दिनेश साहू के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में अनेकों समाज के प्रमुख शामिल थे।

विवेचना कौशल को बढ़ाने नवीनतम कानूनी पहलुओं से रहे अपडेट : प्रशांत

0 एसएसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक 0 नव वर्ष पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और हुड़दंगियों पर सख्ती के दिये निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। यहां जिला पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में साल भर के अपराधों, लंबित मामलों, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की गई और अधिकारियों को पारदर्शी, प्रभावी और संवेदनशील

पुलिसिंग के साथ-साथ डिजिटल पुलिसिंग और जांच में सुधार के निर्देश दिए ताकि अपराध नियंत्रण हो और जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। कानून व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में जिम्मेदारीपूर्वक संवेदनशील होकर कार्य करने एवं आगामी त्यौहार व नववर्ष पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। एसएसपी ने लंबित अपराधों के निकाल पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष समाप्ति की ओर है सभी लंबित केस, चालान, मर्ग और शिकायतों को जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निराकरण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता की समस्याएं

धैर्य से सुनें, उनसे अच्छा व्यवहार रखें और संवेदनशील तरीके से समाधान करें। थानों के कार्यों को डिजिटल बनाने और सीसीटीवीएनएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया



गया। नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। थाना प्रभारियों को कहा कि विवेचना कौशल को बढ़ाने और नवीनतम कानूनी पहलुओं

से अपडेट रहे। खुफिया आधारित पुलिसिंग, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और अपराधियों पर पैनी नजर रखते हुए प्रभावी नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। बेसिक



पुलिसिंग के तहत विवेचकों के साप्ताहिक डायरी के सुपरविजन, बीट प्रणाली में प्रत्येक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने करने के निर्देश दिए। आगामी त्यौहार एवं नववर्ष के अवसर पर संभावित घटनाओं को सही थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

निगाह रखने, सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना के पश्चात उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने हेतु पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए।

यातायात नियमों के उल्लंघन एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, सीएसपी एस.एस. पैकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, डीएसपी अनुप एक्का, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी अभिषेक पैकरा, डीएसपी अजाक पी.डी.कुसूरु सहित जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

गर्भवती महिलाओं हेतु बिहारपुर एवं ओड़गी स्वा.केन्द्र में हुआ विशेष स्वास्थ्य जाँच सत्र

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र ओड़गी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर एस. जयवर्धन के दिशा निर्देशन व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा मार्गदर्शन तथा खंड चिकित्सा ओड़गी डॉ. बंटी बैरागी के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा की अगुवाई में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जाँच सत्र आयोजित किए गए। जिसमें

68 गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क प्रसव-पूर्व देखभाल, विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक दवाएँ उपलब्ध कराया गया, ताकि माँ और शिशु का स्वास्थ्य



सुरक्षित रहे। इस अभियान में एनीमिया, रक्तचाप, शुगर और भ्रूण की जाँच पर जोर दिया जाता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण पहलू है, गर्भवती

महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल सुनिश्चित करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। निःशुल्क जाँच, डॉक्टर के द्वारा बताएँ, दवाएँ, पोषण संबंधी परामर्श, और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान कर उनका प्रबंधन किया गया। एनीमिया, रक्तचाप, वजन, पेशाब और रक्त शर्करा की जाँच की गई। साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं से आग्रह किया गया कि वे प्रत्येक माह के 24 एवं 9 तारीख को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आकर इन सुविधाओं का लाभ

उठाएँ। इस दौरान बिहारपुर, नवाटोला, कुबेरपुर, हथिचुवा, देवडी, पासल, सेमरा, टाड़पाथर, अर्वातिकापुर, खालबहरा सहित पहुँचवर्ती क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं के द्वारा स्वास्थ्य जाँच परीक्षण कराया गया। अभियान को सफल बनाने में डॉ. तरुण सिंह, गीता सहित मितानिन कार्यक्रम के एमटी, मितानिन कार्यक्रम एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।

संपर्क करें
समाचार, ईशतहार, विज्ञापन
हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा
अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

कांकेर में हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का सरगुजा में रहा मिला-जुला असर

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। कांकेर में हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका सरगुजा में मिला-जुला असर देखने को मिला। सुबह से सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अम्बिकापुर शहर में दुकानों को बंद कराया, दोपहर बाद व्यापारियों ने दुकानें खोल दी, क्रिसमस के समय बंद के आह्वान से व्यापारियों में निराशा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं।



इसके बाद सर्व समाज ने गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के सामने सभा का आयोजन किया, जिसमें अजय इंगोले ने कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं

जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा के बाद सर्व समाज की एक रैली कलेक्टोरेट पहुंची, जहां ज्ञान सौंपा गया। ज्ञान में उल्लेख किया गया है कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण की घटनाओं के विरोध में सर्व समाज, छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री को ज्ञान सौंपा है। ज्ञान में सर्व समाज ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी समूहों और भीम आर्मी के तत्वों ने

जनजातीय समाज पर हमले किए, शवों को जबरन दफन किया और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। सर्व समाज ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और प्रदेशव्यापी बंद, धरना का आयोजन किया था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून लागू किया जाए, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान काफी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे।

पॉलीटेक्निक में निःशुल्क डेंटल चेकअप शिविर का आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शासकीय पॉलीटेक्निक की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं सिटी डेंटल हॉस्पिटल, के संयुक्त तत्वावधान में संस्था परिसर में निःशुल्क डेंटल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा समय रहते दांतों से संबंधित समस्याओं को पहचान करना था। शिविर में दंत चिकित्सक डॉ. पृथ्वी शुक्ला एवं डॉ. निक्की सिंह ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने दंत स्वास्थ्य पर आयोजित सेमिनार के माध्यम से सही ब्रशिंग तकनीक, नियमित दंत जांच की आवश्यकता तथा दंत रोगों से बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं का निःशुल्क डेंटल चेकअप करके आवश्यकता अनुसार दवाइयों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य आर.जे. पांडेय ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजन दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी हैं तथा समाज में



सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर को एक सराहनीय पहल बताया। कार्यक्रम का सफल संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अमित कुमार बघेल व व्याख्याता माधुरी तिग्गा ने किया। शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवक युवराज, अभिषेक, दिव्या एवं संस्कृति ने पंजीकरण, व्यवस्था प्रबंधन एवं सट्टा कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर लाभ उठाया। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया।

जहरीले दवा का सेवन किए युवक की इलाज दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भिट्टीकला का बृजपाल पिता सुखदेव गोड 23 वर्ष, बीते 7 दिसम्बर को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को दिए गए बयान में पिता ने बताया है कि उसका पुत्र शराब पीने का आदी था और कामधाम नहीं करता था। घटना दिनांक को सभी खाना खाकर सो गए थे, इस बीच बृजलाल घर नहीं आया था। रात को करीब 8 बजे लघुशंका के लिए बाहर निकला तो बृजलाल घर के पीछे आग के पास बैठकर उल्टी कर रहा था। पास में ही कीड़ा मारने का एक डिब्बा फेंकाया हुआ था। पृष्ठताछ करने पर वह कुछ नहीं बताया। उसके मुह से शराब का महक आ रहा था। परिवार के सदस्यों के सहयोग से वह अपने पुत्र को होली क्रॉस अस्पताल लेकर पहुंचा, यहां इलाज के दौरान 23 दिसम्बर की शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

युवक फांसी लगाकर खुदकुशी किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरपुर में एक युवक फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने बताया घटना के दौरान मृतक जाधर तिकरी पिता स्व. हरिराम 28 वर्ष घर में अकेले था। स्वजन मजदूरी करने के लिए गए थे। काम करके शाम को करीब सात बजे जब वे घर वापस लौटे तो युवक फांसी पर लटका था। इसकी सूचना गांधीनगर थाना में देने पर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम कराया है। मामले में पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।

उचित मूल्य की दुकानों से 64.94 लाख का राशन गबन करने के मामले में दो और गिरफ्तार

तीन आरोपियों को पूर्व में भेजा गया था न्यायिक रिमांड पर

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शहर के घुटरापारा में स्थित उचित मूल्य की दुकानों में गबन के मामले में दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीन आरोपियों को पूर्व में न्यायिक रिमांड पर पुलिस ने भेजा था। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार मिश्रा पिता सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा अम्बिकापुर ने 07.10.2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सहायक खाद्य अधिकारी, के साथ मिलकर जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का संयुक्त रूप से जांच करने पर माह सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में सभी दुकानों में चावल 1631.29 क्विंटल राशि 61,62,267.96 रुपये, शक्कर 10.43 क्विंटल राशि 49,160.62 रुपये तथा चना 48.34 क्विंटल राशि 2,92,692.09 रुपये कुल खाद्यान्न राशि 64,94,120.67 रुपये की कमी पाई गई। जांच में इसके लिए जिम्मेदार उक्त तीनों दुकानों के संचालक, अध्यक्ष पवन सिंह, महिला उपाध्यक्ष, सहायक विक्रेता फरहान सिद्दीकी एवं सैफ अली को पाया गया। रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में धारा 420, 409, 120-बी भा.दं.सं. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 पंजीबद्ध



कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान महिला आरोपिया को 15.10.2025 को, मुकेश यादव को 12.11.2025 को तथा फरहान सिद्दीकी को 04.12.2025 को 13.24 बजे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था एवं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में 23 दिसम्बर को कोतवाली थाना पुलिस को फरार आरोपियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर घेराबंदी करके पवन सिंह पिता स्व. दीप नारायण सिंह 44 वर्ष निवासी घुटरापारा पानी टंकी रोड, सैफ अली पिता इरशाद अली 26 वर्ष, निवासी घुटरापारा पानी टंकी के नीचे को हिरासत में लिया और अग्रिम कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य का जिप सदस्य राधा रवि को मिला दायित्व

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से भाजपा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की गई है। इसमें जिला पंचायत सदस्य राधा रवि को शामिल किया गया है।



राधा रवि ग्राम पंचायत खम्हरिया, ब्लॉक मुख्यालय उदयपुर की निवासी हैं, जो कम समय में ही राजनीति में कदम रखकर बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वे बीए अलावा अध्यक्ष आराध्या जन सेवा समिति, पूर्व संभागीय सचिव रविदास समाज जन कल्याण समिति सरगुजा,

प्रदेश अध्यक्ष सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ का दायित्व संभालते हुए समाज को संगठित कर युवा महिला विंग को मजबूत करने की दिशा में वे सशक्त भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्यों का सफल संचालन किया है। साथ ही महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया है। समाज में एकता, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों को पहुंचाने हेतु वे प्रयासरत हैं।

सरगुजा की विभा चौबे पहुंचीं केबीसी की हॉट सीट तक

साधारण शिक्षिका को अपनी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर मिली उपलब्धि

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले की एक साधारण शिक्षिका ने अपनी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर असाधारण उपलब्धि हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरगुजा जिले की विभा चौबे देश के सबसे प्रतिष्ठित क्रिज शो %कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) की हॉट सीट तक पहुंचने वाली जिले की पहली महिला बन गई हैं। इतना ही नहीं, वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला शिक्षिका होंगी, जो केबीसी के मंच पर हॉट सीट पर बैठकर खेलती हुई नजर आएंगी।



केबीसी द्वारा जारी किए गए पहले प्रोमो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विभा चौबे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों का

सामना करती दिखाई देंगी। प्रोमो सामने आते ही सरगुजा जिले सहित पूरे शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्तमान में विभा चौबे दरिमा गुरुस हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं।

वे वर्षों से छात्राओं को उपलब्धि के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। विभा चौबे की शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। पढ़ने के साथ-साथ निरंतर ज्ञान अर्जन की उनकी को साकार कर सकता है। साधना ही उन्हें केबीसी जैसे राष्ट्रीय मंच तक ले गई। उनकी इस सफलता में परिवार का सहयोग भी अहम रहा है। बल्कि छत्तीसगढ़ की उस बेटी के रूप में हो चुकी हैं, जिसने बच्चों को ज्ञान देते-देते खुद इतिहास रच दिया। उनकी यह उपलब्धि सरगुजा जिले के लिए गर्व, शिक्षा जगत के लिए सम्मान और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है।

पीजी कॉलेज के बैडमिंटन हॉल को खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के हित में खोलने की मांग

आजाद सेवा संघ की पहल पर प्राचार्य ने हॉल की साफ-सफाई के लिए निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शहर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंतर्गत बनारस रोड पर स्थित बैडमिंटन हॉल को खिलाड़ियों के लिए शीघ्र खोलने की मांग को लेकर बुधवार को आजाद सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने महाविद्यालय प्रशासन से मुलाकात की। संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा के नेतृत्व में सौंपे गए औपचारिक ज्ञापन में कॉलेज प्रबंधन का ध्यान खिलाड़ियों को हो रही व्यवहारिक समस्याओं की ओर कराया गया है। संघ के प्रदेश सचिव ने कहा कि वर्तमान में युवाओं के बीच बैडमिंटन के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कॉलेज परिसर में खेल की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध



होने के बावजूद, हॉल का पूर्ण रूप से संचालित न होना समझ से परे है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसाधनों का उपयोग नहीं होने की स्थिति में वे जर्जर होने लगते हैं, ऐसे में छात्रहित व खेल भावना को सर्वोपरि रखते हुए बैडमिंटन

हॉल को नियमित अभ्यास के लिए अविलंब खोला जाना चाहिए, ताकि प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके। महाविद्यालय के प्राचार्य ने आजाद सेवा संघ की मांगों को तर्कसंगत माना। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कॉलेज प्रशासन खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राचार्य ने तत्काल निर्देश देते हुए हॉल की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने कहा। इसके पश्चात इसे खिलाड़ियों और छात्र-छात्राओं के लिए खोल दिया जाएगा। संघ ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा और वे जिला व प्रदेश स्तर पर शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर आजाद सेवा संघ के अन्य पदाधिकारी एवं छात्र उपस्थित रहे।

दोपहिया चालकों से जांच के नाम पर अवैध वसूली

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। कानून व्यवस्था बनाए रखने और जांच के नाम पर इन दिनों कुछ पुलिसकर्मी अपनी जेब भरने में लगे हैं। शाम के समय विशेषकर जब मजदूरों का काम करके वापस जाना होता है, इस दौरान वसूलीबाज कुछ पुलिस कर्मियों की निगाह ऐसे दोपहिया चालकों पर रहती है, जो दिनभर मेहनत करने के बाद अपने घरों की ओर वापस लौटते हैं। इनसे 50-100 रुपये लेकर जेब भरने की धंधा जोरों से चल रहा है। मेहनतकश मजदूर की तमाम मित्रतें मुट्ठी में रुपये पकड़ने तक टिकी रहती हैं। जांच के नाम पर चलने वाली अवैध वसूली इन दिनों बिलासपुर चैक पर कुछ ज्यादा ही हो रही है, जिससे गरीब तबके के मजदूर परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पहले तो दोपहिया चालकों को 500 रुपये चालान पटाने के लिए धौंस दिखाया जाता है, बाद में घर में बच्चों और परिवार के लिए सामान ले जाने के लिए रखे 50-100 रुपये लेने के बाद ही इन्हें विदा किया जाता है। ऐसे वसूलीबाज पुलिस कर्मियों पर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, जो गरीबों को परेशान करके अपनी जेब भरने में लगे हैं।

सोनार समाज ने मासिक बैठक करके स्व. रामचंद्र स्वर्णकार को दी श्रद्धांजलि

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। नवीन सर्व सोनार समाज की मासिक बैठक मंगलवार को जिला अध्यक्ष विनोद सोनी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में समाज को संगठित और इसे विस्तारित करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के शुरुआत में समाज के पुरोधा रहे स्व. रामचंद्र स्वर्णकार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें याद करते हुए समाज के लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते में चलने की प्रेरणा ली। समाज की बैठक हर माह के



अंतिम मंगलवार को लिया गया है। सोनार समाज आयोजित करने का निर्णय दिया कि समाज को नई दिशा देने के लिए सबसे जरूरी है

कि लोग समाज से जुड़े और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। नवीन सर्व सोनार समाज का उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों को संगठन से जोड़ा जाए, ताकि उसके विकास के लिए काम किया जा सके। नवीन सर्व सोनार समाज की बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में सभी पदाधिकारी अपने संगठन का विस्तार न सिर्फ जिले बल्कि पूरे संभाग में करेंगे, ताकि लोगों के जुड़ने से संगठन को

एक मजबूती मिल सके। बैठक में नवीन सर्व सोनार समाज के संभागीय प्रभारी रघुनाथ सोनी, संभागीय संरक्षक शिवराम सोनी, संभागीय अध्यक्ष सुरेश सोनी, जिला अध्यक्ष विनोद सोनी, नगर अध्यक्ष श्रीप्रकाश सोनी, विजय सोनी, सुरेंद्र सोनी, अशोक शिवराम सोनी, सोनी, विनोद सोनी, अंकुर सोनी, अरुण सोनी, सतीश सोनी, शेखर सोनी, अनूप सोनी के साथ बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।